Ministry is that whenever a person appoints an agent it does not involve any assignment or transfer of the rights of the principal in the matter of the contract.

Shri Surendranath Dwivedy: What action have you taken when they have sub-let?

Shri Parimal Ghosh: They have not sub-let; they have appointed an agent and the appointment of an agent does not mean necessarily transferring the right.

Shri Hem Barua: Since Messrs. Wheeler & Company specialises only in the display of those books called shilling-shockers and not books that are worth reading and, at the same time, we know that in their stalls in particular regions the books written in that language or in that particular region are not in display or are not selected there may I know whether Government have seen to this fact that in the matter of selection of books Messrs Wheeler & Company shows a little bit of the orthodoxy and selects books in regional languages also?

Shri Parimal Ghosh: So far as our information goes, they are selling all types of books, including in regional languages.

Shri Hem Barua: They do not

Shri Parimal Ghosh: If so, as the hon. Member has mentioned that point, we will look into it.

Shri Hem Barua: May I submit that whenever I go to a railway station I make it a point to visit the Wheeler & Company stall to examine the books? My knowledge is that their display is limited to a few types of books, mostly sex literature I tell you.

Mr. Speaker: The moment the hon. Member mentioned sex there is so much of commotion in the House. Why did he mention it?

Shri Shashi Ranjan: Just now the hon. Member, Dr. Sen, mentioned that formerly Soviet literature were being rejected and now they are being accepted. May I know from the hon. Minister whether the Communist Party of India have sent their own literature, of the same type, to the railways and whether they have accepted or rejected them?

Mr. Speaker: Next question

Import of Newsprint

\+

*1346. **Shri George Fernandes:**
Shri J. H. Patel:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the amount of money spent annually on the import of foreign newsprint into India; and

(b) the efforts made to increase the production of newsprint in India?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) Total amount of money spent on the import of foreign newsprint was of the order of Rs 693.41, 739 80 618.80. and 976 70 lakhs during 1963-64 to 1966-67 (upto Feb. 1967).

(b) Capacity of the only newsprint mill in the country is being expanded from 30,000 to 75,000 tonnes per annum and the possibility of creating additional capacity in the public sector is being explored. Further to encourage investment in the private sector the newsprint industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, and any party can establish a newsprint plant without a licence under that Act.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक सैक्टर में यह जो न्यूज प्रिन्ट प्लांट है, इस वक्त उसकी पैदावार शायद 30,000 टन सालाना है। करीब सात साल से यह कहा जा रहा है कि उसकी पैदावार 75,000 टन तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यह भी

कहा गया है कि नेपा मिल्ज में इस साल जुलाई तक 75,000 टन की पैदावार हो जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह संकल्प अगले महीने पूरा होने वाला है कि नेपा मिल्ज में 75,000 टन सालाना न्यूज़ प्रिंट तैयार होने लगेगा ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां। हमारा यह संकल्प कार्य रूप में परिणत हो रहा है। वहां पर इमारत वगैरह बनने का काम इस साल अगस्त में शुरू हो जायेगा उसके बाद वहां पर मशीनरी वगैरह लगानी है हम समझते हैं कि मई, 1968 तक कुछ प्राडक्शन भी शुरू हो जायेगा। हमारी आशा है कि 1969 के मध्य तक वहां पर काग़ज़ बनने लगेगा।

श्री जार्ज फरनेन्डीज़ : इसका अर्थ यह है कि इस साल जुलाई तक 75,000 टन पैदावार करने का सरकार का संकल्प तो ख़त्म हो गया और उसमें सरकार बिल्कुल असफल हो गई।

सरकार का संकल्प था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश में न्यूज़ प्रिंट की पैदावार 30,000 टन से 1,50,000 टन तक बढ़ाई जायेगी, लेकिन अभी तक वह 30,000 टन तक ही है। अब कहा गया है कि हम इस सम्बन्ध में निजी क्षेत्र के लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मन्त्री महोदय जानते हैं कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना में निजी क्षेत्र के जितने भी लोगों को लाइसेंस दिये गए थे, उनमें से किसी ने भी लाइसेंस का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए यह साफ़ और स्पष्ट है कि इस देश में न्यूज़ प्रिंट का काम निजी क्षेत्र में होने वाला नहीं है। जब सरकार हर साल न्यूज़ प्रिंट पर दस करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा ख़र्च करती है, तो क्या वह न्यूज़ प्रिंट की पैदावार का काम पूरे तरीके से पब्लिक सैक्टर में लेकर तत्काल इस विदेशी मुद्रा को बचाने का प्रयास करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : इसका उत्तर मैंने शुरू में ही दे दिया है।

श्री कंवरलाल गुप्त : यहां पर दूसरे देशों की जो एम्बेसीज़ हैं, वे जो पीरियाडिकल्ज़ निकालती हैं, उनके लिए वे बाहर से काग़ज़ मंगाती हैं और चूंकि वे अपनी ज़रूरत से ज्यादा कागज़ मंगाती हैं, इसलिए वह काग़ज़ ब्लैक मार्केट में बिकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये एम्बैसीज़ एक साल में कितना काग़ज़ अपने ख़र्च के लिए मंगवाती हैं, क्या उस पर गवर्नमेंट का कोई कण्ट्रोल है कि उस काग़ज़ में से कितना ख़र्च हुआ, कितना ब्लैक मार्केट में बेचा गया और उसके पैसे का क्या हुआ, आदि ?

श्री दिनेश सिंह : हम को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई काग़ज़ एम्बैसीज़ की तरफ़ से काले बाज़ार में बिकता है। अगर माननीय सदस्य यहां या बाहर इसके बारे में कोई सूचना देंगे, तो हम उसकी छानबीन करवायेंगे।

Shri S. R. Damani: What was the reason for the delay in increasing the capacity of NEPA and is there any difficulty about obtaining raw material for the expansion of production?

Shri Dinesh Singh: Now we hope that there will not be any difficulty. I have given a programme as to how we are going to expand. In the past we had to have this matter looked into carefully. As you know, Sir, our desire to manufacture newsprint has been there but we have not been able to get all the raw material. The feasibility studies are now being completed. The House is also aware of the desire to set up a Paper Corporation which will also go into the manufacture of newsprint.

श्री कामेश्वर सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि भारत में अख़बारी काग़ज़ का आयात कब तक बन्द हो जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : इस वक्त मेरे लिए कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है ।

श्री सीताराम केसरी : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय हम को कितने न्यूज़ प्रिंट की आवश्यकता है, कितना हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, कितना हम यहां अपनी फ़ैक्टरी में उत्पादन करते हैं और अपने उत्पादन में हम कितनी वृद्धि करने जा रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : इस वक्त हमारी ज़रूरत 1,70 हज़ार टन की है, जिसमें से फ़िलहाल हम 30 हज़ार टन यहां पर बनाते हैं, जिस को बढ़ा कर 75 हजार टन करने के बारे में मैंने अभी निवेदन किया है । बाकी 100 हज़ार टन हम बाहर से मंगाते हैं और 25 हज़ार टन की आवश्यकता हम सफ़ेद काग़ज़ और दूसरे काग़ज से पूरी करते हैं ।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि बहुत से अख़बार वाले खुद ही इम्पोर्टिड काग़ज़ का कोटा अधिक लेकर उसकी ब्लैक करते हैं और उसको छोटे अख़बारों को काफी पैसा लेकर बेचते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी रोक-थाम की कोई व्यवस्था की है ?

श्री दिनेश सिंह : अगर माननीय सदस्य मुझे इस बारे में सूचना देंगे, तो जरूर इस की जांच करवाई जायेगी ।

Shri Tenneti Viswanatham: In view of such a great shortage of newsprint does the Government think of starting a public sector factory at Bodhan in Nizamabad District of Andhra Pradesh using bagasse as raw material?

Shri Dinesh Singh: The advisability study that has been made does not relate to the State of Andhra. Now that the hon. Member has mentioned this, I am sure the Corporation which will go into this matter will go into that.

Shri P. Venkatasubbaiah: May I know whether there is any proposal with the Government to enter into a bilateral agreement with some of the countries from where we import newsprint in order to save our foreign exchange?

Shri Dinesh Singh: So far as I remember, off-hand, we have some barter arrangement also for newsprint. But I cannot give the details now.

Mr. Speaker: Qs. 844 and 857 may be taken together.

Import of Steel Tubes by the Aminchand Pyarelal Group

+

***844. Shri S. M. Banerjee:**
Shri Madhu Limaye:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri George Fernandes:

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report in the *Patriot* dated the 25th March, 1967 on the Law Ministry's opinion in regard to the import of steel tubes without a licence or a valid licence by the Aminchand Pyarelal Group;

(b) whether Government have held that it is morally/legally justified to amend the licences after the goods have arrived and customs have seized the goods and imposed fines:

(c) if so, whether the whole amending procedure is being re-examined with a view to its revision; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Chenna Reddy): (a) to (d). The news item in the 'Patriot' of March 25 refers to certain imports of sheets. The facts have been stated in reply to Starred Question No. 214 in the Lok Sabha on the 10th November, 1966. The facts briefly are as under:

Three importations by M/s. Aminchand Pyarelal of black plain sheets hot rolled commercial quality of a size